आमोखस व मिडिया की खबरों व प्रथम समाचार पत्र

RNI No. UPHIN/2012/47484

जननायक सम्राट

बर्ष :13 अंक :345 पृष्ठ -4 दिनांक 19 दिसम्बर 2024 दिन गुरूवार

उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस

विरोध–प्रदर्शन में तमाम कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज बुधवार को यूपी विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है, जिसके लिए हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल शाम से ही लखनऊ में पहुंचना शुरू कर दिया है. कांग्रेस दफ्तर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए जुटने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर पार्टी के बड़े नेताओं को रोका जा रहा है. कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को उनके होटल में ही पुलिस ने नजरबंद कर लिया है. यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को लखनऊ में उनके होटल में रोका गया है. उन्हें होटल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. इसे लेकर अविनाश पांडे ने नाराजगी जताई और कहा कि ये सरकार लोगों की आवाज दबाना चाहती है, हम जनता के मुद्दों को उठाना चाहते हैं. लेकिन हमें अपनी बात रखने नहीं दी जा रही है.

अविनाश पांडे को किया नजरबंद

यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को मुद्दाविहीन बताया और कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वो इस तरह से माहौल अपने पक्ष में कर लेंगे तो ये गलत होगी. इसे लेकर जब कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इन मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते आज हम जनता के मुद्दों की आवाज उठाने के लिए यहां संघर्ष कर रहे हैं और हम हर हाल में विधानसभा कूच करेंगे. इस बीच कांग्रेस पार्टी की पार्षद ममता चौधरी को चौक पुल पर पुलिस ने रोक कर हिरासत में ले लिया है. ममता चौधरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय जा रही थी इसी दौरान पुलिस ने पार्षद व उनके साथियों को हिरासत में लिया. कांग्रेस नेता दीपक सिंह को भी रोके जाने की खबर है, जिसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के घर के पास धरना देना शुरू कर दिया.प्रशासन के किए सुरक्षा के इंतजामएक तरफ जहां कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है. कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनके घर और होटलों में ही रोका जा है. कांग्रेसी कार्यकर्ता विधानसभा तक नहीं पहुंच पाएं उसके लिए बड़े–बड़े बैरिकेड्स लगाए है. ये बैरिकेड्स सामान्य बैरेकेड्स से ऊंचे हैं और इन पर ऊपर की ओर नुकीला लोहा लगाया है. पूरे इलाके में धारा 163 लागू की गई है. पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है ऐसे में प्रदर्शन ने विशिष्ट सदस्यों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और कानून व्यवस्था ख़राब हो सकती है.

यूपी में BJP दफ्तर पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा के कैंप कार्यालय पर नगर पालिका का बुलडा.`जर चल ही गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि इसके पहले एक सप्ताह के भीतर भाजपा कैंप कार्यालय को हटाने के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन दो बार गया था, लेकिन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह के विरोध के चलते उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा था. कार्यालय के जमींदोज होने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के काम से जिला कार्यालय गया था, तभी लोगों ने बताया कि कार्यालय टूट गया है. सरकार के लोगों ने तोड़ा है. इसके पहले कोई नोटिस भी नहीं दी गई. जब से यह इंदिरा नगर मार्केट है तब से अपना कार्यालय भी है. भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि सपा सरकार के समय भी कार्यालय तोड़ा गया, मैं धरने पर बैठा तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक हफ्ते में पुनः कार्यालय बनाकर दिया. अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर क्या बैठना. हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था. मेरी कश्ती वहीं डूबी, जहां पानी कम था.क्या लगाया आरोप जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि अतिक्रमण अभियान ठीक नहीं चल रहा है. इससे क्या होना था, जाम भी नहीं लगना था. यहां के जिलाधिकारी की कार्यशैली अच्छी नहीं है. सारे अधिकारियों ने बताया कि डीएम साहब ने कहा कि कार्यालय तोड़ दो. जिलाधिकारी से चार दिन से समय मांग रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं. इस कार्यालय में बहुत से नेता बैठते थे. सपा सरकार के समय आंदोलन की रणनीति यहीं बनती थी. बसपा से भी लड़े और कार्यालय को खाली नहीं होने दिया. कार्यालय अगर बन जाएगा तो समझ लेना कि लोकतंत्र है.उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यालय तोड़ने के पीछे लोगों की सोच है कि कहीं मैं बड़ा नेता नहीं बन जाऊं. कहीं बलिया से टिकट का दावेदार न बन जाऊं. 40 साल विपक्ष में रहकर लड़ा हूं. मैं डरने वाला नहीं हूं. यहां पर अंदरूनी लड़ाई बहुत है. बलिया जिला प्रशासन के पास कोई विजन नहीं है. गरीब इसी कार्यालय में सोते थे.दूसरी तरफ बलिया नगर पालिका के ईओ सुभाष कुमार ने बताया कि जिस स्थल से अतिक्रमण हटाया गया है. वहां एक छोटा पार्क बनाया जाना है. यह जगह पार्क के लिए चिह्नित थी. पहले कैंप कार्यालय नहीं लिखा था. आज लिखा गया. सोमवार तक कार्यालय हटाने के लिए समय मांगा गया था. लेकिन, हटाया नहीं गया तो कार्रवाई की गई.

अमरोहा में मजार के ऊपर निजी स्कूल का निर्माण

SDM ने दिए जांच के आदेश, 3 दिन में मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मजार के ऊपर निजी स्कूल का निर्माण कराने का मामला सामने आया है. आरोप हैं कि बिना नक्शा पास कराए इस स्कूल का निर्माण किया गया है. शिकायत मिलने के बाद उप जिलाधिकारी सदर सुधीर कुमार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और स्कूल प्रबंधन को तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण दिए जाने के निर्देश दिए हैं. खबर के मुताबिक अमरोहा नगर में एक मजार के ऊपर ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल का निर्माण किया गया है. स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की थी, जिसके बाद एसडीएम न इस मामले को संज्ञान में लिया और इसकी जांच के आदेश दिए हैं. बताया जा रहा है कि स्कूल का निर्माण बिना नक्शा पास के किया गया है, जो कि नियमों का उल्लंघन है. प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन भेजा नोटिस प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिस में स्कूल प्रबंधन से पूछा गया है कि क्या उन्होंने स्कूल निर्माण के लिए नक्शा पास कराया है अगर नहीं तो क्यों और स्कूल का निर्माण मजार के ऊपर क्यों किया गया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए उप जिलाधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं. यदि स्कूल प्रबंधन संतोषजनक जवाब नहीं देता है, तो विधिक कार्रवाई की जा सकती है. इस बारे में जब एसडीएम सुधीर कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीते दिनों स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की गई है. जहां मजार भी मिली है. उन्होंने कहा कि स्कूल के मालिक अभी बाहर विदेश में गए हैं जैसे ही वो आएंगे इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्कूल को अपना पक्ष रखने का मौका किया दिया गया है. जवाब के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यूपी की सियासत में 5 महीने में बदल गया गेम

पहले अखिलेश यादव ने रचा इतिहास, फिर बीजेपी ने लिया बदला

उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए अलग–अलग मायनों में महत्वपूर्ण रहा. एक ओर जहां समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कीअगुवाई में इतिहास रचा तो वहीं एक दशक बाद कांग्रेस का राज्य में सूखा खत्म हुआ. दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो साल 2014 से लगातार 60 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर काबिज थी, उसको झटका लगा. बहुजन समाज पार्टी के लिए तमाम को. शिशों के बावजूद नतीजा सिफर रहा. दिल्ली की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, यह बात साल 2024 में साबित कर दी. लोकसभा चुनाव के अप्रत्याशियत परिणाम में सपा ने इतिहास में सबसे ज्यादा 37 सीटें हासिल की. साल 2014 से ही 1–2 सीट के बीच झूल रही कांग्रेस के भी 6 सांसद हो गए. वहीं भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को बड़ा झटका लगा और पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई. राज्य में उसके सहयोगी रहे अपना दल (सोनेलाल) और रालोद ने भी क्रमशः 1 और 2 सीटों पर जीत दर्ज की. लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत सीट शेयरिंग कर चुनाव लड़ा था. लोकसभा में मिली जीत से उत्साहित सपा और कांग्रेस के लिए खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी. 4 महीने के भीतर ही विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुए. सपा ने सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा. कांग्रेस कम से कम 5 सीटें मांग रही थी लेकिन सपा सिर्फ 1–2 सीटों पर राजी थी. इसके बाद पार्टी ने उपचुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया. सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए सपा को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली. कुंदरकी सीट पर बीजेपी ने इतिहास रचा और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद भी जीत हासिल की.सपा सिर्फ करहल और सीसामऊ बचाने में सफल रही. हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले हार जीत का अंतर कम रहा. वहीं बीजेपी ने सात सीटों पर जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव में मिले जख्म को भरने की कोशिश की. बसपा के लिए नतीजा सिफर...उधर, बहुजन समाज पार्टी के लिए लोकसभा में तमाम मेहनत के बाद नतीजा सिफर रहा. बसपा फिर से 0 पर आ गई. वहीं उपचुनाव में भी बसपा के हाथ कुछ नहीं लगा. इसके उलट आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर

सबको चौंका दिया. उन्होंने उपचुनाव में भी प्रत्याशी उतारे लेकिन उसका उन्हें फायदा नहीं हुआ. यूपी में बीजेपी के दो सहयोगी– सुभासपा और निषाद पार्टी के लिए सियासी तौर पर यह साल कुछ खास नहीं रहा. बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में घोसी सीट सुभासपा को दी थी जिस पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद रा. जभर प्रत्याशी थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.वहीं निषाद पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने संतकबीर नगर सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे लेकिन उन्हें भी हार मिली. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि साल 2024 यूपी की सियासत, सियासी दलों और नेताओं के लिए कभी खुशी कभी गम भरा रहा. जहां जून 2024 में सपा और कांग्रेस उत्साहित थे तो वहीं 5 महीने बाद नवंबर मेंबीजेपी की बल्ले–बल्ले थी.

महोबा में PCS परीक्षा की तैयारी के बीच जिला .समन्वय पर्यवेक्षक ने केंद्रों का किया निरीक्षण

उत्तर प्रदेश के महोबा में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है. लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त जिला समन्वय पर्यवेक्षक ने महोबा पहुंचकर सभी 10 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर वहां लाइटे, सीसीटीवी कैमरा, अभ्यर्थियों के बैठने के स्थान आदि का निरीक्षण किया. इस दौरान एसडीएम, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित सेक्टर, स्टैटिक और जोनल मजिस्ट्रेट मौजूद रहे.महोबा जिले में पहली बार लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षा आयोजित की गई है. आगामी 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा को लेकर आयोग हर पहलू पर काम कर रहा है. इसी को लेकर लोक सेवा आयोग ने संतोष कुमार यादव को महोबा का जिला समन्वय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है. पर्यवेक्षक ने आज डीएवी इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जीआईसी, जीआईसी श्रीनगर सहित सभी दस परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया. पीसीएस की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा के जिला समन्वय पर्यवेक्षक संतोष कुमार यादव ने बताया कि महोबा जिले में बनाए गए 10 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4128 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. प्रथम पाली में सुबह 09:30 से 11:30 बजे एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 02:30 बजे से सायं 04:30 बजे तक आयोजित की जायेगी. परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिले के नोडल अधिकारी मृदुल चौधरी ने सेक्टर, स्टैटिक, जोनल मजिस्ट्रेट एवं केन्द्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक करते हुए लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन करने के निर्देश दिए.परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराया जाएगा परीक्षा के जिला समन्वय पर्यवेक्षक संतोष यादव ने बताया कि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया है. जिसमें परीक्षा केंद्रों के प्रवेश से लेकर परीक्षा कक्ष का निरीक्षण किया गया. जहां अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उस कक्षों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था, अभ्यार्थियों के बैठने का सीट प्लान, परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूरी कड़ाई के साथ सम्पन्न कराया जाएगा. इस दौरान कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रतिबन्धित सामग्री न ले जाए पाये, जिसको लेकर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने–अपने परीक्षा केन्द्रों पर कड़ाई से निरीक्षण करने के निर्देश दिये गए हैं. इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जा सके.

जनरल की बमबारी में मौत, मास्को ने कहा- पश्चिम के अपराधों को उजागर कर दिया

रूस के रेडियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस फोर्सेज के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की मंगलवार सुबह दक्षिण–पूर्वी मॉस्को में हुए बम विस्फोट में मौत हो गई। शीर्ष रूसी नेताओं ने इस अपराध के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी अधिकारियों ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हा.ंने यूक्रेन और अन्य जगहों पर पश्चिम के ष्अपराधोंष को लगातार उजागर किया है। विज्ञापन आरटी की रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट सुबह करीब 6 बजे दक्षिण–पूर्वी मॉस्को में रियाजान्स्की एवेन्यू पर एक आवासीय इमारत के बाहर हुआ, जब किरिलोव और उनके सहयोगी आधिका.रिक वाहन में सवार होने के लिए परिसर से बाहर निकल रहे थे। विज्ञापन रूसी

जांचकर्ताओं ने कहा कि इमारत के प्रवेश द्वार के पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर टीएनटी युक्त एक आईईडी लगाया गया था और संभवतः रेडियो सिग्नल या मोबाइल फोन द्वारा दूर से विस्फोट किया गया था। विस्फोट से खिड़कियां टूट गईं, इमारत का प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन नष्ट हो गया। हत्या, आतंकवाद और अवैध हथियारों की तस्करी के आरोपों के तहत एक आपराधिक जांच शुरू की गई है और जांच समिति के प्रमुख, अलेक्जेंडर बैस्ट्रीकिन व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे हैं।

मंथरा का काम न करें, मंत्री एके शर्मा ने सदन में कुछ ऐसा कहा कि सीएम योगी को आई हंसी

विधानसभा समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह और बिजली मंत्री एके शर्मा के बीच दिलचस्प जुबानी जंग देखने को मिली, जब सपा विधायक ने उन्हें बिजली और मीटर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की. इसके जवाब में एके शर्मा ने कहा कि वो उनके और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में मंथरा वाला काम न करें, क्योंकि वो दिल्ली सबसे कम जाने वाले नेता है और जो भी करते हैं मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से करते हैं. दरअसल गाजीपुर की जमनिया सीट से सपा विधायक ओम प्रकाश ने बिजली को लेकर मंत्री एके शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये तो ऊपर वाले हैं, जनता से चुनाव लड़कर आएंगे तो पता चलेगा. मुख्यमंत्री से बात करिए और कुछ अच्छा काम करिए. हम समझ रहे हैं कि आपकी वकालत कहीं और से हैं. उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था. मंथरा वाला काम न करें सपा विधायक सपा विधायक के इस बयान के जवाब में एके शर्मा ने उनको ये

मालूम नहीं कि मैं सबसे कम दिल्ली जाने वाले नेताओं में हूं, माननीय मुख्यमंत्री इसके साक्षी है. ये मंथरा वाला काम हमारे और मुख्यमंत्री के बीच में न किया जाए क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर करते हैं. उनके मार्गदर्शन में करते हैं. मैं जो भी कहूंगा या करूंगा उसमें अक्षरस जब तक सीएम का आदेश और निर्देश नहीं होगा वो मेरे मुंह से नहीं निकलेगा. आप इस बात की तसल्ली करें. एके शर्मा ने इस दौरान सपा विधायक पर तंज भी कसा और कहा कि ओम प्रकाश जी कहते हैं कि वो पीते नहीं है लेकिन मुझे मालूम है कि वो नशे में रहते हैं. क्योंकि गाजीपुर में नशे का एक और इंतजाम है वहां एक प्राकृतिक उत्पाद मिलता है उसके चलते ही वो नशे में रहते हैं. एके शर्मा जब सपा सदन में ये बयान दे रहे ते उनके आगे बैठे सीएम योगी भी मुस्कुरा रहे थे.

विश्व हिन्दू परिषद ने किया जस्टिस शेखर यादव का बचाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने और अल्पसंख्यकों को लेकर दिए बयान को लेकर हुए विवाद के बीच टभ्च के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने उनका बचाव किया है. उन्होंने कहा कि परिषद वैसे तो आम तौर पर रिटायर जजों को ही बुलाता है. लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है. टभ्च नेता मिलिंद परांडे ने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद अक्सर अपने कार्यक्रमों में रिटायर जजों को आमंत्रित करते हैं. हम अपेक्षा करते हैं कि रिटायर लोग सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का काम करेंगे लेकिन, सेवा में रहने वाले मौजूदा लोगों से हम किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं करते. वैसे जस्टिस शेखर यादव ने अपने संबोधन में कुछ भी गलत नहीं कहा था. उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम में पेंडिंग है, इसलिए इस बारे में ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं होगा. जस्टिस शेखर यादव ने दी सफाई इससे पहले मंगलवार को जस्टिस शेखर यादव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने भी पेश हुए थे, जहां जस्टिस संजीव खन्ना के कॉलेजियम के सामने अपनी बात रखते हुए सफाई दी. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक

उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि उनके संबोधन को पूरे संदर्भ में नहीं समझा गया बल्कि उनकी स्पीच के कुछ हिस्सों को उठाकर विवाद खड़ा कर दिया गया है.

इस दौरान जस्टिस खन्ना ने उन्हें अपने पद की गरिमा का ख्याल रखने को कहा. पांचों जजों ने कहा कि न्यायाधीश का हर बयान पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए ताकि उससे लोगों का न्यायपालिका में विश्वास प्रभावित न हो. बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जज शेखर यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यकों की भावनाओं के हिसाब से चलेगा. उन्होंने मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का भी इस्तेमाल करते हुए कई ऐसा बातें कहीं, जिन पर विवाद खड़ा हो गया. इसे लेकर उनके खिलाफ महाभियाग चलाने और जज के पद से हटाए जाने की भी मांग भी की गई है.

वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगी।पीठ ने कहा, बेहतर होगा कि आप उन्हें समझाएं कि हमारे हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए।रिटायर्ड जजों को मिल रही 6 से 15 हजार रुपये पेंशन

पीठ ने कहा कि इस मामले पर अलग–अलग मामलों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा और शीर्ष अदालत जो भी आदेश देगी, वह सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू होगा। पीठ ने मामले की सुनवाई 8 जनवरी के लिए स्थगित कर दी।

पिछले महीने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि कुछ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मात्र 6,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की मामूली पेंशन मिल रही है।पीठ एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी,जिन्होंने कहा था कि उन्हें 15,000 रुपये की पेंशन मिल रही है।याचिकाकर्ता, जिन्हें जिला न्यायालय में 13 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, ने दावा किया था कि प्राधिकारियों ने पेंशन की गणना करते समय उनकी इलाहाबाद के न्यायाधीश ने लगाए आरोपन्यायिक सेवा पर विचार करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था, अगर हमारे सामने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जिन्हें 6,000 रुपये और 15,000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो यह चौंकाने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है?मार्च में एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन लाभों की गणना में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वे बार या जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुए हैं।इसमें कहा गया था कि जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन लाभ की गणना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके अंतिम वेतन के आधार पर की जानी चाहिए।

डिप्टी सीएम ने किया ऐलान

विधायकों के लिए अच्छी खबर हैं. जल्द ही उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय टोल टैक्स के झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है. जिसके बाद उन्होंने टोल से छूट के लिए न तो अपनी पहचान बतानी होगी और न ही उन्हें अपना आईकार्ड, पहचान पत्र या कोई पास दिखाना नहीं पड़ेगा. उनकी गाड़ियों पर अब मुफ्त फास्ट टैग लगाया जाएगा, जिसके बाद वो नेशनल हाईवे पर फर्राटा भरते हुए निकल सकेंगे.यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी विधान परिषद में सरकार की ओर सभी विधायकों को ये आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा प्रदेश में जितने भी विधायक है उनकी गाड़ियों पर जल्द ही फ्री फास्ट टैग लगाया जाएगा, जिससे वो टोल टैक्स पर बिना पास दिखाए ही सफर कर सकेंगे. मौर्य ने कहा कि वो इस संबंध में सड़क परिवहन एवं रा. जमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखेंगे और यूपी के विधायकों को ये सुविधा दिलाएंगे.

केशव प्रसाद मौर्य ने दिया जवाब

दरअसल यूपी विधान परिषद में निर्दलीय सदस्य आकाश अग्रवाल ने सरकार से ये सवाल पूछा था, जिसका जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये स्थिति ठीक नहीं है कि विधायकों को टोल

प्लाजा पर सत्यापन के लिए इंतजार करना पड़े. इसलिए जल्द ही विधायकों के लिए फ्री फास्ट टैग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. आकाश अग्रवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि दो दिसंबर को जब वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से होते हुए जा रहे थे तो रास्ते में फतेहाबाद टोल प्लाजा पर उन्हें रोक लिया गया. इस दौरान टोल संच.ालक ने पांच मिनट तक उन्हें रोककर जांच की और उनके साथ अभद्रता भी की गई गई. जिसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ती नंदी को निर्देश दिए कि वो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच कराएं और इस पर क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी भी सदन को दें.

इतनी कम पेंशन, स्थिति दयनीय है, रिटायर्ड जजों की अर्जी पर केंद्र पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की पेंशन को लेकर निराशा जताई। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को महज 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है। यह बेहद दयनीय स्थिति है।न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, आप हर मामले में कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। कभी–कभी, आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है।पीठ ने कहा, यह दयनीय है। पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवा.निवृत्त न्यायाधीशों को 10,000 से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिल रही है। बता दें कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन से संबंधित मुद्दे को उठाने वाली याचिकाएं बुधवार को पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थीं। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अनुरोध किया कि इस पर जनवरी में सुनवाई की जाए।सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की।

सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला निकला बांग्लादेशी, शाहीनबाग में छिपा, नोएडा पुलिस ने यूं दबोचा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को नोएडा की सेक्टर 39 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नोएडा पुलिस ने ये गिरफ्तारी दिल्ली के शाहीन बाग से की है. आरोपी का नाम शेख अता उल है. जो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है.पुलिस के मुताबिक कुछ साल पहले शेख अता उल बांग्लादेश से पश्चिन बंगाल के मालदा आकर रहने लगा. और फिर मालदा से दिल्ली आ गया और शाहीन बाग इलाके में रहने लगा. पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए है. इतना ही नही जिस मोबाइल के जरिये इसने धमकी भरा वीडियो डाला था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

जान से मारने की धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल. नोएडा पुलिस ने बीएनएस और आईटी एक्ट में मामला दर्ज शुरू की थीं जांच. नोएडा पुलिस सोशल मीडिया पर धमकी

भरे इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक्शन बोर्ड में आ गई थी. तुरंत नोएडा के सेक्टर 39 में मुकदमा दर्ज किया गया. सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में आरोपी योगी आदित्यनाथ की कुर्बानी देने की बात कहता दिख रहा है और सांप्रदायिक भावना भडकाने वाली टिप्पणी भी कर रहा है. नोएडा के एडिशनल डीसीपी मनीष मिश्रा ने बताया की आरोपी सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो में देश में संवैधानिक पद पर बैठे जननेता के संबंध में आपत्तिजनक, झूठे और भडकाऊ बातें कह रहा था. जिनसे करोडों भारतीय नागरिकों की आस्था जुडी है. आरोपी ने अलगाववादी और भडकाऊ बातें करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया है.नोएडा पुलिस आरोपी शेख अताउल का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है. साथ ही पुलिस यह भी पता लग रही है कि आखिरकार बांग्लादेश से हिंदुस्तान कैसे पहुंचा था. वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी भारत सीमा में दाखिल होने में मदद की थी.

अंबेडकर पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने पीएम मोदी से की अमित शाह के इस्तीफे की मांग

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री के भाषण को आपत्तिजनक बताया है। खरगे ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री ने गलत बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। खरगे ने कहा कि पीएम मोगी गृहमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। खरगे ने कहा कि अमित शाह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।बता दें कि संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ष्ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते। वे मनुस्मृति की बात करते हैं। पीएम मोदी ने अमित शाह का बचाव करने के लिए 6 ट्वीट किए। इसकी क्या जरूरत थी? अगर कोई बीआर अंबेडकर के बारे में गलत कहता है, तो उसे कैबिनेट से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन वे दोस्त हैं और एक–दूसरे के पापों का समर्थन कर रहे हैं।जानिए क्या है पूरा मामला?दरअसल, कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि संविधान पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी दिखाती हैं कि भाजपा और आरएसएस के नेता बीआर आंबेडकर से कितनी नफरत करते हैं। पार्टी ने मांग की कि शाह अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगें।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग मनुस्मृति में विश्वास करते हैं वे निश्चित रूप से आंबेडकर से असहमत होंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शाह के राज्यसभा में भाषण के अंश एक्स पर साझा किए।इसमें शाह विपक्ष पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं, श्अभी एक फैशन हो गया है– आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर.. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।श्जयराम ने अपनी पोस्ट में कहा, श्नफरत इतनी है कि उन्हें बाबा साहब के नाम से भी चिढ़ होती है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहब के पुतले जलाते थे, जो खुद बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को बदलने की बात करते थे।श्श उन्हा.ंने कहा, श्श्शर्मनाक! अमित शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।राज्यसभा में अमित शाह ने दिया था संबोधन कांग्रेस के लिए संविधान का अर्थ सिर्फ इतना था कि सत्ता में बने रहने के लिए जब चाहो संशोधन कर दो। तुष्टीकरण की शुरूआत भी इसीलिए हुई थी। तीखे स्वर में उन्होंने कांग्रेस से कहा– यदि कांग्रेस आज मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन कर रही है तो फिर पूरा शरीया ही क्यों नहीं दे दिया। निकाह और वारिस के लिए पर्सनल लॉ चाहिए तो अपराध में क्यों नहीं? अपराध करने पर पत्थर मारोगे, सूली पर चढ़ाओगे?शाह ने कहा कि भाजपा ने जब कभी संशोधन किया तो देश के लिए किया। उत्तराखंड की भा.जपा सरकार ने मॉडल यूसीसी बनाया है। इसकी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के बाद भाजपा सरकार इसे सभी राज्यों में लागू करेगी।

AMU के प्रोफेसर का गजब का कारनामा

फर्जी तरीके से 20 बार की साथी प्रोफेसर की शिकायत

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जहां पहले छात्रों के गुट आपस में भिड़ा करते थे. वहीं अब प्रोफेसरों का आपस में भिड़ना एक आम बात हो गया है. बीते दिनों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विभाग में ही दो प्रोफेसर के आपस में मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. जिसमें एक प्रोफेसर के द्वारा लिखित शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा मुक. दमा भी पंजीकृत कर लिया गया. अब उस मामले में जांच ही चल रही है, तो वही एक अजीबो गरीब मामला अभी सामने आया है.अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा दूसरे प्रोफेसर को लेकर 20 से ज्यादा बार शिकायत की है. कुछ शिकायत पत्र अलीगढ़ एसएसपी को डाक से भेजे गए हैं तो कुछ शिकायत पत्र अलग–अलग अधिकारियों को प्रेषित किए गए. जब एक ही मामले में 20 से ज्यादा बार शिकायत पहुंची तो पुलिस भी असमंजस में पड़ गई. दूसरे प्रोफेसर की शिकायत पर पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया. इस दौरान पुलिस ने जांच में पाया की एक ही प्रा. फेसर के द्वारा अलग–अलग नाम से कई शिकायत की है. जब पुलिस के द्वारा पूरे मामले में जांच की गई तो शिकायतकर्ता प्रोफेसर के द्वारा पहले पुलिस को असमंजस में रखा, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी दिखाएं तो मामला उजागर हो गया. वहीं पूरे मामले की जानकारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन को दी गई. इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा प्रोफेसर को नोटिस देते हुए जल्द ही

जवाब मांगा है.विभाग के अन्य प्रोफेसर ने झूठी शिकायतें दर्ज कराईदरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के केमिस्ट्री विभाग का है. जहां 16 नवंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के के. मिस्ट्री विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. इशात मोहम्मद खान ने शिकायत दर्ज करवाई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विभाग के एक अन्य प्रोफेसर, रियाजुद्दीन, हिंदू और मुस्लिम छात्राओं के नाम पर कई झूठी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं. अब तक उन्होंने 20 से अधिक शिकायतें डाक के माध्यम से प्रशासन को भेजी हैं. रियाजुद्दीन द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर पर परीक्षा और पेपर से संबंधित अनियमित. ताओं के साथ–साथ धार्मिक मुद्दों को लेकर आरोप लगाए गए. इस संदर्भ में डॉ. खान ने एएमयू प्रशासन और पुलिस से संपर्क किया और पोस्ट ऑफिस की एक फुटेज बतौर सबूत जमा की. इसमें रियाजुद्दीन को शिकायतें पोस्ट करते और रसीद लेते हुए देखा जा सकता है.पहले इनकार, फिर कबूलनामाप्रोफेसर रियाजुद्दीन से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने प्रारंभ में सभी आरोपों को खारिज कर दिया. उनका कहना था कि पोस्ट ऑफिस जाना सामान्य बात है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उन्होंने कोई शिकायत डाली है. हालांकि, जब पुलिस ने उन्हें डाकघर की फुटेज और समयानुसार रसीदें दिखाईं, तो उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया. इस कबूलनामे का ऑडियो–वीडियो सबूत एएमयू प्रशासन को सौंपा गया है. अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा एएमयूएएमयू के कुलसचिव इमरान खान ने प्रोफेसर रियाजुद्दीन को अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया है. यदि वे जवाब नहीं देते हैं, तो इसे उनकी चुप्पी माना जाएगा. यदि रियाजुद्दीन दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ यूजीसी के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस मामले ने एएमयू में शैक्षणिक और प्रशास. निक प्रक्रियाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह विवाद न केवल व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला प्रतीत होता है, बल्कि संस्थान की छवि पर भी नक. ारात्मक प्रभाव डालता है. एएमयू प्रशासन इस मामले को निष्पक्ष तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है.

बकायेदारों पर नगर निगम की वसूली की कार्यवाही–नगर निगम सम्पत्ति कर समय से जमा न करना पड़ रहा भारी–जोन–3 में सीलिंग व वसूली की कार्यवाही।

अलीगढ़ नगर निगम की गृह कर वसूली को बढ़ाने के लिए प्रयासरत अलीगढ़ नगर आयुक्त विनोद कुमार के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव के नेतृत्व में नगर निगम के सभी जोन में बड़े बकायेदारों के विरुद्ध ताबड़तोड़ सीलिंग और ताला. बंदी की कार्यवाही जोनल अधिकारियों के नेतृत्व में लगातार की जा रही है।अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने बताया कि बड़े बकायेदारों से सम्पत्ति कर वसूली के लिये नगर निगम द्वारा युद्धस्तर पर अभियान चलाकर सीलिंग व मौके पर वसूली की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।बुद्धवार को जोन–3 में उप नगर आयुक्त अमित कुमार और गृहकर टीम की मौजूदगी में तालाबंदी की

कार्यवाही की गई जिसमें एडीए कॉलोनी शांति निकेतन स्थित सगीर भवन संख्या 9क्ड पर रु.141000.00 से रु.50000.00 एडीए शांति निकेतन स्थित आमिर स्टील भवन संख्या 276,5 पर रु.104742.00 से :.30000.00 एडीए शांति निकेतन स्थित मौ आजाद भवन संख्या 35DM पर :.147508.00 से :.30000.00 एवं एडीए शांति निकेतन स्थित असलम भवन संख्या 220सी 256 पर :.194451का बकाया होने पर की तालाबंदी एवं वसूली की कार्यवाही की गयी।नगर आयुक्त विनोद कुमार ने करदाताओं से अपील है दिसम्बर, 2024 के समाप्त होने से पूर्व अपने संपत्ति कर का भुगतान जमा करें और छूट का लाभ उठाएं

सराय रहमान स्थित 49 वर्ष पुराने शिव मन्दिर को कराया कब्जा मुक्त

अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सराय रहमान इलाके में एक मंदिर जर्जर अवस्था में मिला है. बताया जा रहा है कि यह मंदिर सालों से बंद पड़ा था. हाल ही में प्रशासन की देखरेख में दोबारा खोला गया है. यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और लगभग 45 सालों से भी अधिक पुराना बताया जा रहा है. मंदिर के आसपास मुस्लिम समुदाय के घर होने की वजह से यह मामला धार्मिक और सामाजिक संवे. दनशीलता का विषय बन गया था. स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मंदिर सालों से बंद था. इस मंदिर के आसपास का इलाका मुस्लिम बहुल है और समय के साथ मंदिर उपेक्षा का शिकार हो गया. करणी सेना और हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के जरिये अवैध कब्जा किया गया है. मंदिर के लंबे समय से बंद होने और इसके आसपास की भूमि पर मुस्लिम आबादी होने को लेकर हिंद. ूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि मंदिर की कथित मूल भूमि पर कब्जा किया गया है.जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शनहिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि मंदिर की जानबूझकर उपेक्षा की गई, जिससे यह समुदाय के धार्मिक महत्व को कम कर सके. इस मुद्दे को लेकर करणी सेना और अन्य संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. फिलहाल प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है. अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार और थाना बन्ना देवी पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर स्थिति जायजा लिया. इसके बाद प्रशासन की देखरेख में मंदिर का दरवाजा खोला गया और उसकी साफ–सफाई की गई. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मंदिर में कुछ पुरानी मूर्तियां रखी हुई थीं. मंदिर की साफ–सफाई के बाद इसे पूजा–अर्चना के लिए तैयार किया गया. हालांकि, इस प्रक्रिया में प्रशासन को स्थानीय मुस्लिम समुदाय से किसी प्रकार के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा.मंदिर बंद होने की ये है वजह स्थानीय मुस्लिम समुदाया के लोगों ने कहा कि मंदिर के आसपास कोई अवैध कब्जा नहीं है. उनका कहना है कि यह मंदिर सालों पहले खाली हो गया था, जब यहां रहने वाले कुछ हिंदू परिवार अपनी जमीन बेचकर कहीं और चले गए. लोगों ने बताया कि मंदिर की मूर्तियां भी संबंधित परिवार अपने साथ लेकर चला गया. मुस्लिम समुदाय के मुताबिक, मंदिर में पूजा–अर्चना बंद हो जाने के कारण यह मंदिर उपेक्षित हो गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मुद्दे को कुछ संगठनों द्वारा जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, जिससे इलाके में सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके.हिंदूवादी संगठनों ने किया ये दावा दूसरी ओर करणी सेना और हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि मंदिर पर लंबे समय से मुस्लिम समुदाय का दबदबा है, जिसकी वजह से स्थानीय हिंदू समुदाय मंदिर तक पहुंचने में असम. र्थ था. उनका यह भी दावा है कि मंदिर के आसपास और भी ऐसी जमीन हो सकती है, जो मंदिर की मूल संपत्ति का हिस्सा है. इन संगठनों ने प्रशासन से अपील की है कि मंदिर की जमीन की खुदाई की जाए और अगर मंदिर से संबंधित अन्य संपत्तियां मिलें तो उन्हें भी हिंदू समुदाय को सौंपा जाए.मंदिर पर प्रशासन ने क्या कहा? अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि यह मंदिर एक छोटा सा कमरा है, जिसमें कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम का इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है. इस मामले में जिला प्रशासन को अधिक जानकारी है और वही इस पर आगे की कार्रवाई करेगा.

शिवमहापुराण के प्रथम दिन धूमधाम से .निकली कलश यात्रा

अलीगढ़। आज गांधी वाड़ा कनवरीगंज से गौशाला में विशाल महाशिवपुराण का आयोजन धूमधाम से मनाया जा रहा है उसे पूर्व कलश यात्रा का आयोजन बहनें पीले वस्त्र पहने सैकड़ो की संख्या में और भाई बंधु समिति के सभीपदाधिकारी भोलेबाबा का दुपट्टा पहने हुए बहुत ही शोभायात्रा में मग्न थे ऐसा लग रहा था काशी नगरी अपनी अलीगढ़ में ही स्थापित हो गई हो कलश यात्रा लक्ष्मी नारायण लक्ष्को के नेतृत्व में पूज्य दीदी कृष्ण प्रिया ने अपने हाथों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया कलश यात्रा राधे राधे भजन मंडली के द्वारा सुमित गोटेवाल, गोपाल ने पूरी रास्ता भजन गाते हुए हरिगढ़ को काशी वृंदावन मथुरा बना दिया कलश यात्रा गांधी वाड़ा से कनवरीगंज कटरा गुड़िया बाग लकड़ी की ताल से नंदन अभिनंदन होते हुए देहली गेट चौराहे से खैर रोड होते हुए गौशाला पहुंची सभी भक्तों ने भोले बाबा के भजन गाकर गौशाला को काशी विश्वनाथ का मंदिर बना दिया और उसके उपरांत सभी ने भोजन प्रसादी की 2रू00 बजे से भोले बाबा का आगमन हुआ और शिव महापुराण का शुभारंभ हुआ अविनाश कॉल और लक्ष्मी नारायण लक्ष्को ने कहा कि अलीगढ़ की दो मंजिल प्रथम गौशाला बिना सरकारी अनुदान के चल रही है 600 के करीब को वंशों का पालन पोषण हो रहा है गौ माता के भजन की ही निमित्त यह कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष होता है अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता ने अलीगढ़ की जनता से आह्वान किया गौशाला में 2रू00 बजे से 5रू00 बजे तक अपना समय भोले बाबा के गौ माता के चरणों में देकर पूज्य कृष्ण प्रिया दीदी के मधुर वाणी से भोले बाबा की महिमा का गुणगान सुने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं भोले बाबा का गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें पूज्य दीदी ने आज प्रथम दिन शिव महापुराण का महत्व बताया और कहा सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है शिव भोले बाबा इस दुनिया के पालनहार संरक्षक कर्ता है कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण लक्ष्को, अविनाश कोल, राजेंद्र प्रसाद नूतन लॉक, दीपक गुप्ता, उमेश ऑटोमोबाइल्स,राकेश, अतुल हार्डवेयर, श्याम कपड़े वाले, मीडिया प्रभारी विशाल देशभक्त, अतुल, विमल गुप्ता, ममता गुप्ता, प्रभा सिंह, कंचन, इंदुबाला, यतेंद्र डिब्बा, अरुण अचार वाले, मधु कुसुम, लता बंदना सीमा वाला, कंचन सैकड़ो की संख्या में भक्त मौजूद रहे।

सीडीओ ने स्वच्छ कुंभ-स्वस्थ कुंभ का पोस्टर किया जारी

अलीगढ़ महाकुंभ सनातन संस्कृति एवं उसकी एकता का विराट स्वरूप है।यह उद्गार मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने मॉ लीलावती सेवा ट्रस्ट के श्स्वच्छ कुंभ–स्वस्थ कुंभश्श पोस्टर को अपने कार्यालय कक्ष में जारी करते हुए व्यक्त किए।मॉ लीलावती ट्रस्ट वृंदावन द्वारा महाकुंभ के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए श्स्वच्छ कुंभ–स्वस्थ कुंभश्श का पोस्टर तैयार कराया गया है, जिसका लोकार्पण बुधवार को सीडीओ प्रखर कुमार सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ केवल धार्मिक, पौराणिक ही नहीं आध्यात्मिक आस्था का भी केंद्र है।ट्रस्ट की बाल व्यास गौसुता वृंदा किशोरी ने कहा कि महाकुंभ समाज के विभिन्न रंगों को एक सूत्र में पिरोता है। बाल व्यास भैया बृज किशोर ने बताया कि यह पर्व हमें पूर्वजों से आध्यात्मिक धरोहर के रूप में मिला है।इस अवसर पर वृंदावन से आए महंत सोनू शर्मा, आजादी का अमृत महोत्सव के जिला समन्वयक सुरेन्द्र शर्मा समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से विकास कार्यों की बैठक संपन्न

अलीगढ़ जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में सीएम डैश बोर्ड पर प्रदर्शित होने वाली विकास योजनाओं के सबंध में माह नवंबर की रैंकिंग के आधार पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद को समय से मिले। सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से मुख्यालय पर निवास करते हुए समय से कार्यालय उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व विभागीय अधिकारियों का है।डीएम ने फैमिली आईडी ई श्रेणी में होने एवं कार्य की शिथिल प्रगति पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि 15 दिसंबर से आरंभ हुए ग्राम पंचायतवार कैम्प में 31 दिसंबर तक फैमली आईडी के लिए डाटा एकत्र करना है, कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित अधिकारी के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि क्षेत्र भ्रमण कर फैमिली आईडी के कार्य में तेजी लाई जाए। डीएम ने ग्रामों में लग रहे किसानों के रजिस्ट्रीकरण शिविर के दौरान भी फैमिली आईडी बनाए जाने के साथ ही सभी पंचायत सेक्रेटरी को नियमित रूप से उपस्थित रहकर कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृत्व शिशु एवं बा. लिका मदद योजना में ई श्रेणी आने पर श्रम विभाग को कार्य सुधार के निर्देश दिए।बैठक में कुल 75 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने श्श्ए प्लसश्श पाने वाले अधिकारियों के कार्य की सराहना करते हुए अन्य ग्रेडिंग वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट कर कार्य सुधार की चेतावनी दी। उन्होंने सीवीओ समेत सभी खण्ड विकास अधिकारियों एवं नगर निगम को निर्देशित किया कि शीतलहरी एवं ठण्ड से बचाव के लिए गौशालाओं में सुमुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने सत्यापन के लिए लंबित आवेदन पत्रों की सूची एसडीएम को देने के निर्देश दिए ताकि सत्यापन संभव हो सके। समाज कल्याण अधिकारी को लाभार्थीपरक योजनाओं के सफल संचालन के लिए शिविर लगाने के निर्देश देते हुए लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। हर घर नल– हर घर जल योजना में सड़क पुनरोद्धार कार्य समय एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग के करने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए गए।बैठक में सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, सीएमओ डॉ नीरज त्यागी, पीडी डीआरडीए भाल चंद त्रिपाठी, डीडीओ आलोक आर्य, उप कृषि निदेशक यशराज सिंह समेत विकास विभाग से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे।

सूर्य का सुपरफ्लेयर पृथ्वी के लिए है गंभीर खतरा, तबाह हो सकती है दुनिया

नई खोज में वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

सूर्य की रौशनी से पृथ्वी रौशन होती है. धरती पर गर्मी का एहसास होता है. साथ ही धरती पर कई और तरह के ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य होता है. लेकिन सूर्य से अविश्वसनीय रूप से बड़ी ऊर्जा की तरंगे भी निकलतीं हैं, जो पृथ्वी के लिए बेहद गंभीर समस्या बन सकती है. उन्हें सौर सुपरफ्लेयर कहा जाता है. दुनियाभर के वैज्ञानिक धीरे–धीरे इसका अध्ययन करते हुए इसे लेकर चिंतित हो रहे हैं. क्योंकि पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि ये सूर्य में ये घटनाएं लगभग एक हजार साल में एक बार होती है. लेकिन हाल ही में उन्हें ये पता चला है कि अंतरिक्ष में ये घटनाएं अक्सर होती है. सूर्य के सुपरफ्लेयर हमारे लिए इसलिए चिंता के विषय हैं क्योंकि हम सैटेलाइट, जीपीएस और पावर ग्रिड जैसी बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक बड़ी सौर ज्वाला इन सभी चीजों को एक बार में गड़बड़ कर सकती हैं. अब सवाल यह है कि क्या हम सौर ज्वाला से होने वाली समस्याओं के लिए तैयार हैं?ऊर्जा के विस्फोट हैं सौर ज्वालाएंसौर ज्वालाएं ऊर्जा के विस्फोट हैं, जिन्हें सूर्य खुले अंतरिक्ष में निष्कासित कर देता है. सूर्य की मामूली सौर ज्वाला सरलता से पृथ्वी के लिए मामूली व्यवधान को पैदा कर सकती है. जिसमें रेडियो सिग्नल या जीपीएस सेवा में गड़बड़ी हो सकती है. हालांकि, एक सौर सुपरफ्लेयर बेहद शक्तिशाली होता है. नियमित फ्लेयर की तुलना में इसमें लाखों गुना अधिक ऊर्जा निकलेगी. बता दें कि ये विस्फोट प्रकाश की गति से चलते हैं, जिसे अंतरिक्ष में पृथ्वी तक पहुंचने में बस चंद मिनट का ही समय लग सकता है.धरती पर सौर सुपरफ्लेयर से आ सकती हैं कैसी दिक. कतेंसूर्य की छोटी सौर ज्वाला पृथ्वी पर कई अस्थायी समस्याएं पैदा करती हैं. लेकिन वहीं एक सुपरफ्लेयर बेहद विनाशकारी हो सकती है. जो अंतरिक्ष में सेटैलाइटों को भी तबाह कर सकता है, बिजली ग्रिडों को बंद कर सकती है. साथ ही दुनियाभर के संचार माध्यमों को भी खराब कर सकती है और ये समस्या कई दिन, हफ्ते या महीनें तक भी रह सकती है. जिससे लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं पैदा हो सकती है. नए अध्ययन में हुआ खुलासाडॉ. वैलेरी वसीलीव ने दिसंबर 2024 में साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में उन्होंने 50 हजार से ज्यादा सितारों के डेटा की जांच की. उन तारों को करीब 100 वर्षों में एक बार सुपरफ्लेयर का अनुभव होता है. इस नई खोज ने वैज्ञानिकों के लिए चिंता पैदा कर दी है.

कनाडा में इमिग्रेशन प्रक्रिया होगी सख्त, स्थायी निवास के नियमों को कड़ा करने की है योजना

कनाडा की इमिग्रेशन अथॉरिटी अस्थायी या स्थायी निवास के आवेदकों के पास नौकरी का प्रस्ताव होने पर अतिरिक्त मिलने वाले लाभ को समाप्त करने पर विचार कर रही है, जो कनाडा में निवास को लेकर धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. यह जॉब ऑफर्स लेबर मार्केट इंपैक्ट असेस्मेंट (स्ंइवनत डंतामज प्उचंबज ेमे. उमदज – स्डप्।) के तहत आते हैं, जो इंप्लोयर की ओर से विदेशी श्रमिक को नियुक्त करने से प्राप्त करने वाला एक दस्तावेज है.स्थायी निवास (च्त) हासिल करने के इच्छुक आवेदकों के लिए जॉब ऑफर होने पर उनके स्कोर में कम से कम 50 अंक जोड़े जा सकते हैं, जो एक्सप्रेस एंट्री केटेगरी के तहत क्वा. लिफाई करने की संभावना को बढ़ा देते हैं.इमिग्रेशन मंत्री ने बदलाव को लेकर की घोषणाकनाडा के इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीजनशिप मंत्री मार्क मिलर ने मंगलवार (17 दिसंबर) को ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कनाडा के इमिग्रेशन के नियमों में संभावित बदलाव की घोषणा की है. इस दौरान मिलर ने कहा, 'सरकार कार्यक्रम की अखंडता को मजबूत करने और स्डप्। धोखाधड़ी को कम करने के लिए अतिरिक्त उपायों को लागू करने की योजना बना रही है. जिसमें जॉब ऑफर के कारण एक्सप्रेस एंट्री के लिए उम्मीदवारों को मिलने वाले अतिरिक्त प्वॉइंटस को हटाना शामिल है. 'मिलर ने आगे कहा, ष्यह उपाय कैंडिडेट्स को स्डप्। खरीदने के लिए प्रेरित करने वाली प्रोत्साहन को समाप्त करेगा. जिससे सिस्टम में निष्पक्षता बढ़ेगी.ष्स्डप्। धोखाधड़ी कनाडा में बनी चर्चा का विषयस्डप्। धोखाधड़ी हाल के महीनों में कनाडा में चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि सरकार इमिग्रेशन को कंट्रोल करने और इसके पूरे सिस्टम को पूर्ण रूप से सुधारने के लिए प्रयास में लगी हुई है.कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि कुछ बेईमान इमिग्रेशन एजेंट्स इंप्लायरों के साथ मिलकर तैयार करते हैं. जिसके बदले उन्हें कर्मचारी 10,000 कनाडाई डॉलर से लगभग 75,000 कनाडाई डॉलर तक की राशि चुकाते हैं. कुछ संभावित प्रवासियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को स्डप्। की प्रोसे. सिंग के लिए किए जाने वाले मांगों के जानकारी दी है.

सऊदी ने धमकाया तो थरथर कांपा पाकिस्तान, 4,300 भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला

अब पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद बल्कि अपने देश के भिखारियों को लेकर भी दुनियाभर में बदनाम हो गया है. मध्य पूर्व के कई देश तो पाकिस्तानी भिखारियों से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने शहबाज सरकार को चेतावनी तक दे दी है. पूरी दुनिया से आ रही शिकायत के बाद अब पाकिस्तान ने भिखारियों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. शहबाज सरकार ने भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है. 4,300 भिखारियों को ब्लू में डालासऊदी अरब समेत कई देशों की शिकायत के बाद शहबाज सरकार ने 4,300 भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है. इसका मतलब ये हुआ कि जिन भिखारियों का नाम इस लिस्ट में है वो अब देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. आपको बता दें कि हाल ही में सऊदी ने पाकिस्तान की सरकार से शिकायत की थी कि हज और उमराह वीजा लेकर लोग वहां आ रहे हैं और मक्का मदीना में भीख मांग रहे हैं. इस कारण सऊदी में भिखारियों की संख्या बढ़ गई है. सऊदी की नाराजगी के बाद पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया है जिसकी जानकारी मोहम्मद बिन सलमान की सरकार को दी गई है.पाकिस्तान ने सऊदी अरब को दी जानकारीपाकिस्तान के गृह मंत्री मो. हसिन रजा नकवी ने भिखारियों की ब्लू लिस्ट के बारे में सऊदी अरब को जानकारी दी. सऊदी के डिप्टी इंटीरियर मंत्री नासिर बिन अब्दुलअजीज अल दावूद को लिस्ट में दर्ज नामों की सूचि सौंपी गई.सऊदी ने दी थी चेतावनी. सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वह उमराह और हज वीजा के तहत यात्रा करने वाले भिखारियों पर गंभीरता से और तत्काल संज्ञान ले. रियाद ने इस्लामाबाद के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से कहा था कि वह ऐसे ला. ेगों को मिलने वाले वीजा पर रोक लगाए. सऊदी सरकार ने अपनी चेतावनी में कहा कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक देश में भीख मांगते पकड़े गए. उन्हें वापस भेज दिया गया. रियाद के मुताबिक ये पाकिस्तानी भिखारी उमराह और हज वीजा के तहत सऊदी अरब में दाखिल हुए थे और अपना समय मक्का और मदीना की सड़कों पर भीख मांगने में बिता रहे थे. सऊदी ने कहा था कि यदि स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका पाकिस्तानी उमराह और हज यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

रूस का बड़ा ऐलान, कहा- हमने बना ली कैंसर की वैक्सीन, सबके लिए निःशुल्क होगी उपलब्ध

आज पूरी दुनिया कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है. ऐसे में रूस ने एक ऐसा दावा किया है जो पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है. रूस ने कहा कि उसने एक कैंसर वैक्सीन बना ली है जो सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी. सोमवार (16 दिसंबर) को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने कैंसर के खिलाफ एक टीका विकसित किया है जिसे 2025 की शुरुआत से रूस के कैंसर रोगियों को मुफ्त में लगाया जाएगा. रूसी राज्य के स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी ज्ै के अनुसार, रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के जनरल डायरेक्टर एंड्री काप्रिन ने रूसी रेडियो चौनल पर इस वैक्सीन को लेकर जानकारी दी.मॉस्को में गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड मा. इक्रोबायोलॉजी के निदेशक, अलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग ने पहले टीएएसएस को बताया था कि टीका ट्यूमर के विकास को रोक सकता है और कैंसर को फैलने से रोक सकता है. यह टीका स्पष्ट रूप से आम जनता को कैंसर से बचाव के लिए दिए जाने के बजाय कैंसर रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. ये टीका हर तरह के कैंसर रोगी को दिया जा सकता है. अन्य देश में भी लगी टीका विकसित करने की होड़ रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय समेत रूसी राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान रेडियोलॉजिकल केंद्र और गामालेया राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने घोषणा की पुष्टि की और स्पष्ट किया कि टीका कैसे काम करता है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि टीका किस कैंसर का इलाज करेगा, यह कितना प्रभावी है या यहां तक कि टीके को क्या कहा जाएगा. यह वैज्ञानिक रूप से संभव है कि कैंसर को लक्षित करने के लिए किसी प्रकार का टीका विकसित किया गया हो. अन्य देश भी फिलहाल कुछ इसी तरह का विकास करने पर काम कर रहे हैं.बाजार में पहले से कैंसर टीके मौजूद साल 2023 में यू.के. सरकार ने व्यक्तिगत कैंसर उपचार विकसित करने के लिए एक जर्मन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया. इसके अलावा फार्मास्युटिकल कंपनियां मॉडर्ना और मर्क एंड कंपनी वर्तमान में त्वचा कैंसर के टीके पर काम कर रही हैं. बाजार में पहले से ही ऐसे टीके मौजूद हैं, जिनका लक्ष्य कैंसर को रोकना है, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के खिलाफ टीके, जो सर्वाइकल कैंसर को रोकने में मदद करते हैं.

7.3 तीव्रता के भूकंप से वानुआतु में मची तबाही, अब तक 14 की मौत, सैकड़ों घायल

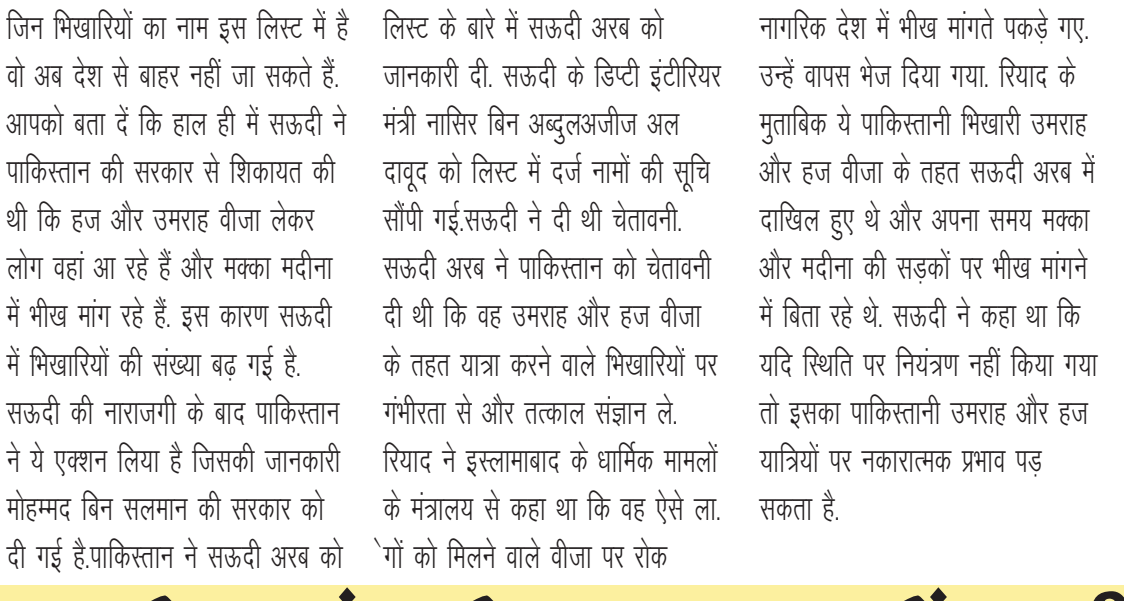

दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप समूह वाला देश वानुआतु में मंगलवार (17 दिसंबर) की सुबह करीब सवा 7 बजे 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, इससे देश में काफी तबाही मची है. भूकंप का केंद्र वानुआतु के मुख्य द्वीप इफाते से 30 किलोमीटर दूर समुंदर के अंदर 57 किलोमीटर गहराई में था. इस भूकंप की वजह से अभी तक वानुआतु में 14 लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं.अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार, प्रारंभिक भूकंप के बाद भी क्षेत्र में कई झटके महसूस किए गए हैं. इसमें बुधवार (18 दिसंबर) की सुबह में 5.5 तीव्रता का एक झटका भी शामिल है. स्थानीय पुलिस ने कहा कि वानुआतु में 'स्टेट ऑफ इमरजेंसी' लगाई गई है. जिससे कि लोगों की आवाजाही को सीमित किया जा सके.ऑस्ट्रेलिया के डीएफएटी विभाग ने क्या कहा?ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग (डीएफएटी) ने कहा कि उसे इस क्षेत्र में कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों की होने की जानकारी है. वहीं, विदेश मंत्री पेनी वोंग ने मंगलवार (17 दिसंबर) की रात एक बयान में कहा कि भूकंप से वानुआतु में काफी नुकसान हुआ है और ऑस्ट्रेलिया बुधवार को सहायता सामग्री भेजेगा.ऑस्ट्रेलिया के 9न्यूज नेटवर्क ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यालय ने कहा है कि पोर्ट विला में एयरपोर्ट और बंदरगाह तक पहुंचने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे सहायता पहुंचाने के प्रयास प्रभावित हो सकते हैं.अमेरिकी समेत अन्य दूतावासों की इमारतों को पहुंचा नुकसानवानुआतु की राजधानी पोर्ट विला में अमेरिका और कई अन्य देशों कदूतावास की इमारतों को भी भूकंप से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है. हालांकि अभी तक भूकंप से हुए नुकसान का पूरा आकलन नहीं किया जा सका है.बता दें कि भूकंप आने के बाद सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था. सरकारी और अन्य संस्थाओं की वेबसाइट्स भी बंद हो गई थीं. इंटरनेट बंद हो गया था. कई बिलि. डंग गिरी और उनके मलबे में कई गाड़ियां भी दबी है.सक्रिय भूकंप क्षेत्र में आता है वानुआतुवानुआतु दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में 80 छोटे–छोटे द्वीपों का एक देश है. ये फिजी के पश्चिम और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है. ये सारा इलाका एक सक्रिय भूकंप क्षेत्र में आता है और यहां बड़ी संख्या में भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं.

आवश्यकता है
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र जननायक सम्राट के लिए जिला व्यूरो चीफमंडल व्यूरो चीफ ब्लाक ,ब्यूरो संवाददाता की आवश्यकता है।
सम्पर्क करें –
अमित कुमार वर्मा –संम्पादक
मौः–8218049162,8273402499

जननायक सम्राट
हिन्दी साप्ताहिक
मालिक,मुद्रक, प्रकाशक आरती वर्मा द्वारा आशु प्रिंटिंगप्रेस,अचलताल अलीगढ़ से मुद्रितकराकर . कार्यालय सरोज नगर गली नम्बर 5,अलीगढ़ से प्रकाशित
सम्पादक–अमित कुमार वर्मा
सभी विवाद का न्याय क्षेत्र जनपद अलीगढ़ न्यायलय ही होगा